International Journal of Education and Science Research Review
E-ISSN 2348-6457
Volume-6, Issue-2, March-April – 2019
P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org
Email- editor@ijesrr.org

अनुसूचित जातियों की कल्याणकारी नीति एवं कार्यक्रम का अध्ययन

Varsha
Research scholar Singhania University
Jhunjhunu, Rajasthan

Dr. Rajbir singh
HOD Department of Political Science
G.G.D.S.D. College, Palwal Haryana

सार

1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, भारत सरकार ने यह दृष्टिकोण बनाया कि आरक्षण जैसे विभिन्न स्रोतों द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के मुख्य उद्देश्य के साथ योजनाओं और कार्यक्रमों को तैयार करना महत्वपूर्ण है। और इन तीन समुदायों के उन्नयन के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना। यह सरकार की एक मानक नीति रही है जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सामान्य आबादी के बराबर लाना है। इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाओं को समझना है। योजनाओं के कार्यान्वयन से शिक्षा, रोजगार के अवसर, आवास, परिवहन के साधन, वित्तीय सहायता आदि में सुधार हुआ है। इन समुदायों का आर्थिक विकास गरीबी की स्थिति को कम करके और अन्य सामाजिक समूहों के साथ संचार के विकास के द्वारा किया जाता है।

मुख्य शब्द: कल्याण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, योजनाएं, कार्यक्रम, समुदाय

परिचय

भारत एक कल्याणकारी देश है। देश के भीतर लागू किए गए कार्यक्रमों और नीतियों का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों के विकास और कल्याण की ओर अग्रसर होना है, विशेष रूप से वंचित और हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर ध्यान केंद्रित करना। भारत के संविधान की प्रस्तावना, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार और विशिष्ट खंड, यानी अनुच्छेद 38] 39 और 46] राज्य की अपने लोगों के प्रति प्रतिबद्धता की गवाही देते हैं। अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के सामाजिक रूप से वंचित समूहों ने अपने समुदाय और आर्थिक प्रगति के लिए समय की अवधि में विशेष जोर दिया है। सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के तीव्र सामाजिक.आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त पर्यावरणीय परिस्थितियों के निर्माण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों की संरचना और कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उपयुक्त नीतियां तैयार करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन समुदायों के कल्याण के लिए अलग.अलग लक्ष्योन्मुख कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें धन का निर्धारण, सब्सिडी का प्रावधान, रोजगार के अवसरों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य प्रशिक्षण केंद्रों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण) शामिल हैं।

2011 की जनगणना के अनुसार, तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 107-12 लाख थी, जो कुल जनसंख्या का 19-18% थी। अनुसूचित जनजातियों की संख्या 5-74 लाख है जो कुल जनसंख्या का 1-03% है। इन समुदायों

के लिए प्राथमिक गतिविधियों को शैक्षिक विकास, आर्थिक विकास, आवास और अन्य योजनाओं, विशेष घटक योजना और जनजातीय उप योजना के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (एससीपी) और अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजातीय उप योजना (टीएसपी) के कार्यान्वयन ने उनकी शुरुआत के बाद से विशेष जोर दिया है, क्योंकि ये कार्यक्रम अन्य से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए धन के आनुपातिक प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए परिचालन तंत्र हैं। सामान्य विकास क्षेत्र (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, एनडी)।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पिछड़ेपन के कारण

एससी, एसटी और ओबीसी वंचित अवस्था में हैं। इन समुदायों के पिछड़ेपन के मुख्य कारण इस प्रकार बताए गए हैंरू (नीतियां, कार्यक्रम और योजनाएं, एन.डी.)। गरीबी . गरीबी सबसे प्रचलित स्थितियों में से एक है जो इन समुदायों के पिछड़ेपन का कारण बनती है। यह उनके जीवन यापन को बनाए रखने के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों के अधिग्रहण के मार्ग में एक बड़ी बाधा रही है। गरीबी की स्थितियाँ तब उत्पन्न होती हैं जब व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय कम होती है और दैनिक जीवन की सभी आवश्यकताओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। ये समुदाय काफी हद तक गरीबी और संसाधनों की कमी की स्थितियों से प्रभावित हैं, जिसके कारण वे शिक्षा के महत्व को महसूस नहीं कर पाते हैं। वे केवल सिरों को पूरा करने के लिए नौकरी के अवसर तलाशने के लिए संघर्ष करते हैं। मुख्य कारण यह है कि ये समुदाय गरीबी से त्रस्त हैं, वे भूमिहीन हैं, उनके पास कोई उत्पादक संपत्ति नहीं है और उनके पास स्थायी रोजगार और रहने की स्थिति तक पहुंच नहीं है।

शारीरिक और सामाजिक अलगाव . ये समुदाय अन्य समुदायों से शारीरिक और सामाजिक रूप से अलग.थलग हैं। गरीबी, अशिक्षा और पिछड़ेपन की स्थिति उन्हें शारीरिक और सामाजिक रूप से अन्य समुदायों से अलग करने में सक्षम बनाती है। अन्य सामाजिक समूहों के साथ इन व्यक्तियों का संचार या तो कम है या पूरी तरह से अनुपस्थित है। भौतिक अलगाव की जड़ें सामाजिक.सांस्कृतिक अलगाव में हैं, ये शुद्धता और प्रदूषण के नियमों पर आधारित हैं और अस्पृश्यता के अभ्यास में परिलक्षित होते हैं। शैक्षणिक संस्थानों में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति अभी भी कक्षा सेटिंग के भीतर भेदभाव महसूस कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में इन समुदायों के व्यक्तियों को अलग.अलग बर्तनों में भोजन और पानी दिया जाता है, उन्हें फर्श पर बिठाया जाता है और अन्य सभी चीजें अलग.अलग रखी जाती हैं जो उनके द्वारा उपयोग की जाती हैं। ऐसे उदाहरण भी सामने आए हैं, जब इन समुदायों के साथ अन्य समुदायों के व्यक्तियों, जैसे कि स्कूल के शिक्षक या घरों के अन्य लोग आदि द्वारा दुर्व्यवहार, मारपीट और दबाव डाला जाता है। भेदभावपूर्ण व्यवहार का अनुभव उनके पिछड़ेपन की ओर ले जाता है।

सूचना और जागरूकता का अभाव . इन समुदायों से संबंधित व्यक्तियों के पास या तो शिक्षा का निम्न स्तर है या बिल्कुल भी शिक्षा नहीं है। मुख्य रूप से उनमें जानकारी और जागरूकता का अभाव है। इन कारणों से वे उच्च या मध्यम वर्ग के व्यक्तियों के साथ संवाद करने में असुरक्षित महसूस करते हैं। जागरूकता और ज्ञान व्यक्तियों में अपने घरों से बाहर निकलने और बाहरी दुनिया में जाने और लोगों के साथ बातचीत करने के लिए आत्मविश्वास पैदा करता है। सूचना और जागरूकता की कमी को प्रमुख बाधा माना जाता है जो इन समुदायों को एकांत में रहने में सक्षम बनाता है। इसलिए, इस समस्या को कम करने के लिए, इन व्यक्तियों के बीच शिक्षा और साक्षरता कौशल के विकास के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना महत्वपूर्ण है। शिक्षा और साक्षरता कौशल के विकास के अलावा, सभी व्यक्तियों के लिए प्रभावी संचार कौशल विकसित करना महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई है, जहाँ माता.पिता, जिन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं की है, अपने बच्चों को विद्यालय भेज सकते हैं।

रोजगार के अवसरों की कमी . ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्ति प्रमुख व्यवसाय के रूप में कृषि पर निर्भर करते हैं और दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते हैं। श्रमिकों की इस प्रकार की नौकरियां कम आय उत्पन्न करती हैं, जो उनके रहने की

स्थिति को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। उनके पिछड़ेपन के लिए उचित नौकरियों और रोजगार के अवसरों की कमी काफी हद तक जिम्मेदार है। जब इन व्यक्तियों के पास आय के उचित स्रोत नहीं होते हैं, तो वे अपने आप को पिछड़ा हुआ और झिझक महसूस करते हैं। वे पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, चिकित्सा सुविधाओं आदि की दैनिक जरूरतों और आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। ये समुदाय ज्यादातर अल्पसंख्यक नौकरियों में लगे हुए हैं, जो उनके लिए किसी भी प्रगति या विकास के अवसरों का प्रावधान नहीं करते हैं। माता.पिता अपने बच्चों की शैक्षिक और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होते हैं, जैसे कि किताबें, स्टेशनरी, वर्दी, आदि, जिसके परिणामस्वरूप स्कूल छोड़ना पड़ता है। इसलिए, रोजगार के अवसरों की कमी न केवल उनके पिछड़ेपन की स्थिति का कारण बनती है, बल्कि शिक्षा प्राप्त करने में भी उनकी अक्षमता होती है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए चलाए गए कार्यक्रम

एससी, एसटी और ओबीसी के कल्याण के मुख्य उद्देश्य के साथ शुरू किए गए कार्यक्रम मुख्य रूप से संगठनों के साथ. साथ शैक्षणिक संस्थानों द्वारा शुरू किए जाते हैं। इन्हें निम्नानुसार कहा गया हैरू प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (पीईसी) लिमिटेड . एससी, एसटी और ओबीसी के संबंध में सरकार के निर्देशों और निर्देशों का संगठन द्वारा उचित रूप से पालन किया जाता है। कर्मचारी संवर्ग के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समूह के कर्मचारियों के लिए योग्यता अवधि में पदोन्नति के प्रत्येक चरण में एक वर्ष की कटौती समयमान पदोन्नति योजना के तहत दी जाती है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी), दिल्ली और कोलकाता केंद्र . आईआईएफटी ने वर्षों से अपने मूल दृष्टिकोण के साथ अपनी शिक्षण, अनुसंधान और प्रशिक्षण क्षमताओं को संरेखित करके अंतरराष्ट्रीय व्यापार शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है और लगातार अकादमिक श्रेष्ठता उत्पन्न करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसे भारत के शीर्ष बिजनेस स्कूलों में मजबूती से स्थान दिया गया है। आईआईएफटी आरक्षण से संबंधित सरकारी निर्देशों का पालन करता हैय एससी, एसटी और ओबीसी के लिए विशेष भर्ती अभियान के तहत ग्रुप ए और सी में पदोन्नति के लिए विज्ञापन अप्रतिबंधित थे। सीधी भर्ती एवं विभागीय पदोन्नति हेतु चयन समितियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उपयुक्त प्रतिनिधि होते हैं।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग (आईआईपी) . यह संस्थान एससी और एसटी समुदायों से संबंधित योग्य उम्मीदवारों के लिए पैकेजिंग में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में प्रवेश के लिए सीटें आरक्षित करता है। पैकेज कोर्स में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवारों के लिए छात्रवृत्ति की एक योजना भी है। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (ITPO) . प्ज्च् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के कल्याण के लिए समय.समय पर जारी किए गए भारत सरकार के दिशा.निर्देशों का पालन करता है।

—षि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) .APEDA को किसी भी SC] ST] OBC या महिला कर्मचारियों से किसी भी प्रकार की अनसुलझी शिकायत नहीं मिली है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायतों पर विचार करने के लिए एपीडा में महिला अधिकारियों सहित उप महाप्रबंधक रैंक के एक अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति बनती है।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) . एमपीईडीए द्वारा एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों के संबंध में उपयुक्त आरक्षण नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। इन श्रेणियों के कल्याण की देखभाल के उद्देश्य से एक संपर्क अधिकारी का चयन किया गया है। संपर्क अधिकारी के माध्यम से निर्दिष्ट श्रेणियों द्वारा दिए गए अभ्यावेदन उचित रूप से सुविचारित हैं। खनिज और धातु व्यापार निगम (एमएमटीसी) लिमिटेड . एमएमटीसी में आरक्षित श्रेणियों का उपयुक्त प्रतिनिधित्व है। संगठन में एक एससी और एसटी सेल मौजूद है। आरक्षित श्रेणियों को स्वीकार्य आरक्षण और अन्य उद्यमों के संबंध में सरकार के आदेशों और निर्देशों की सहमति सुनिश्चित करने के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय में एक उप महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है और प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (ईसीजीसी) लिमिटेड . अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और पदोन्नति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीधी भर्ती के मामले में भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी समूहों में आरक्षण प्रदान किया जाता है। इन व्यक्तियों द्वारा अनुभव की जाने वाली किसी भी प्रकार की शिकायतों से संबंधित शिकायतों की रोकथाम और निवारण के लिए एक शिकायत समिति भी है। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसटीसी) . एसटीसी एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों में रोजगार के लिए सरकारी निर्देशों के अनुसार अपेक्षित आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए बेंचमार्क मानदंड में कमी प्रदान की जाती है। आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को स्टाफ संवर्ग में ग्रेड.1 से कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु टंकण परीक्षा में टंकण गति में पांच प्रतिशत की कमी प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों को समय.समय पर विशेष तैयारी और प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। नई दिल्ली में निगम द्वारा संरक्षित आवासीय अपार्टमेंट के आवंटन के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों को वरीयता दी जाती है।

महिलाओं का कल्याण . महिलाओं का कल्याण करने के लिए कार्यस्थल पर शिकायतों और शिकायतों की रोकथाम और निवारण महत्वपूर्ण है। उन्हें उचित सहायता और मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए जो उन्हें सही दिशा की ओर ले जा सके। महिलाओं का कल्याण और आर्थिक विकास व्यक्तियों का प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों से संबंधित। इन महिलाओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए उपायों और योजनाओं को लागू करना महत्वपूर्ण है। उन्हें पढ़ने, लिखने और संख्यात्मक समस्याओं को हल करने के बुनियादी साक्षरता कौशल को बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, उनका सशक्तिकरण लाना महत्वपूर्ण है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के तहत योजनाएं

पंचवर्षीय योजनाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। पहली योजना (1951.56) के माध्यम से 1951 में शुरू की गई विकास योजना में यह कल्पना की गई थी कि प्रगति के विभिन्न क्षेत्रों के तहत कार्यक्रम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों सहित जनसंख्या के सभी वर्गों की सहायता करेंगे, लेकिन अनुपयुक्त रूप से, यह ऐसा कभी नहीं हुआ। दूसरी योजना (1956-61) ने यह सुनिश्चित करने का बीड़ा उठाया कि असमानता को कम करने के लिए आर्थिक विकास की सहायता समाज के मध्यम रूप से कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के लिए अधिक से अधिक जमा हो। तीसरी योजना (1961-66) ने अवसर की बड़ी समानता और आय और धन के अंतर में कमी और आर्थिक शक्ति के समान वितरण को प्रोत्साहित किया। चौथी और पाँचवीं योजना (1967-78) ने स्रोत उद्देश्य की परिकल्पना की, प्रक्रियाओं के माध्यम से व्यक्तियों की जीवन स्थितियों की नियमितता में तेजी से वृद्धि के रूप में जो समानता और सामाजिक न्याय को भी प्रोत्साहित करती है। बाद की वार्षिक योजना (1970-80) की महत्वपूर्ण संरचनाओं में से एक अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (एसपीसी) के विशिष्ट उपकरण की शुरुआत थी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये समूह अन्य विकास क्षेत्रों से लाभ का उचित हिस्सा प्राप्त करते हैं। छठी योजना (1980-85) ने अनुसूचित जातियों के विकास के दृष्टिकोण में बदलाव को चिह्नित किया। अनुसूचित जातियों के लिए हाल ही में शुरू किए गए एससीपी के आवेदन को विशेष महत्व दिया गया। सातवीं योजना (1985-90), राज्य योजनाओं, केंद्रीय योजना और विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) से एससीपी के तहत अनुसूचित जातियों के विकास के लिए धन के प्रवाह में काफी वृद्धि हुई।

सातवीं योजना में प्राथमिकता अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास को देना था। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) का प्रमुख उद्देश्य अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यक तथा समाज के अन्य वर्गों के विकास के बीच की खाई को पाटना और दृढ़ संकल्प पर ध्यान केंद्रित करना था। यह कल्पना की गई थी कि अनुसूचित जातियों के अधिकारों के दमन, अस्पृश्यता, न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करने आदि सभी प्रकार के उत्पीड़न की अवहेलना की

जाएगी, ताकि वे सभी विकासात्मक प्रयासों का लाभ उठा सकें। अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ी जातियों एवं अल्पसंख्यकों के आर्थिक विकास हेतु।

केंद्र सरकार की योजनाएं

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सघनता को सामाजिक असमानता और अन्याय से बचाना सरकार का संवैधानिक दायित्व है। केंद्र सरकार समाज के सामाजिक.आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं प्रदान करती है। केंद्र द्वारा समर्थित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएँ है।

1. विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, जैसे आईएएस, आईपीएस आदि के लिए कोचिंग और प्रशिक्षण को विभिन्न सेवाओं और रोजगार के अवसरों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में सुधार लाने के लिए आवश्यक माना जाता है।
2. उच्च शिक्षा में छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की शुरूआत की जाती है। उच्च शिक्षण संस्थानों में इन व्यक्तियों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है और पोस्ट.मैट्रिक छात्रवृत्ति की उपलब्धता उनके सीखने की सुविधा प्रदान करती है।
3. जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता को बढ़ावा देने के प्राथमिक उद्देश्य के लिए, विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और उन क्षेत्रों में शैक्षिक केंद्रों की शुरुआत करना, जहाँ साक्षरता की दर कम है।
4. विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाली अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु छात्रावासों का निर्माण।
5. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास और समस्याओं में अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठित सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थानों को वित्तीय सहायता।
6. चिकित्सा और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पाठ्यपुस्तकों का प्रावधान करना, और विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्तियां और यात्रा अनुदान।

राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राजीव गांधी फैलोशिप सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित और वित्तपोषित है। यह योजना उन उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों से संबंधित हैं और जो विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान में नियमित और पूर्णकालिक एम.फिल और पीएचडी डिग्री जैसे उच्च अध्ययन करने की आकांक्षा रखते हैं। इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी। अनुसूचित जाति के लिए 1333 स्लॉट और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 667 स्लॉट हर साल सभी विषयों के लिए हैं। आयोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना के लिए विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता का प्रावधान कर रहा है। इन प्रकोष्ठों का उद्देश्य आरक्षण नीति को लागू करने में विश्वविद्यालयों को सहायता का प्रावधान करना है। छात्र.छात्राओं के प्रवेश एवं विभिन्न स्तरों पर शिक्षण एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के नियोजन के संबंध में आरक्षण नीति के क्रियान्वयन के संबंध में।

आदिवासी कल्याण कार्यक्रम

भारत के संविधान ने अनुसूचित जनजातियों और जातियों के विकास के लिए प्रावधान किया है जो पिछड़ी स्थिति में हैं और इस प्रकार इन जातियों को विभिन्न विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए उपयुक्त बनाया गया है। 1951 में एक आदिवासी कल्याण विभाग का उद्घाटन और लॉन्च किया गया था। इसके काम को सुपरसीड करने के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों जैसे संगठनों के माध्यम से

सरकार द्वारा किए गए सामान्य विकास कार्यक्रमों के पूरक के रूप में पेश किया गया था। योजना अवधि के दौरान, केंद्र सरकार ने निम्नलिखित योजनाओं को प्रायोजित किया।

1. आदिवासी विकासखण्ड।
2. जनजातीय सहयोग समितियां।
3. आदिवासी लड़कियों के लिए छात्रावास।
4. जनजातीय छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां।
5. प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण।
6. अनुसंधान, प्रशिक्षण और विशेष परियोजनाएं।

जनजातीय अनुसंधान संस्थान

जनजातियों और उनकी समस्याओं का गहन अध्ययन करने के लिए विभिन्न राज्यों में शोध संस्थान स्थापित किए गए हैं। आदिवासी समुदाय आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं, जहां वे विभिन्न पहलुओं से अनभिज्ञ हैं और विभिन्न प्रकार की आधुनिक और नवीन तकनीकों से अपरिचित हैं। वे आम तौर पर अपने लिए प्रदान करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प बनाना, कृषि और खेती का अभ्यास करना और वस्तु विनिमय प्रणाली वे व्यवसाय हैं जिनमें वे लगे हुए हैं। आदिवासी समुदाय एक साधारण जीवन जीते हैं और उनके विकास के लिए उपायों को लागू करना महत्वपूर्ण है।

ये आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों में स्थापित किए गए हैं। कुछ संस्थानों में आदिवासी कलाकृतियों को प्रदर्शित करने वाले संग्रहालय भी हैं। इन संस्थानों का उपयोग राज्य और केंद्र सरकार द्वारा अनुसंधान, शिक्षा, डेटा संग्रह, प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशालाओं, आदिवासी उप.योजनाओं की तैयारी में पेशेवर इनपुट, आदिवासी प्रथागत कानूनों के प्रकाशन आदि के लिए किया जा रहा है।

ट्राइबल कोऑपरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया

ट्राइबल को.ऑपरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1987 में भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति समुदायों को उनकी लघु वन उपज और अधिशेष, कृषि उपज के लिए विपणन सहायता और लाभकारी कीमतों का प्रावधान करने और उन्हें हतोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य से की गई थी। शोषक निजी व्यापारियों और बिचौलियों से दूर। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि जनजातीय समुदायों का शोषण न हो या उन्हें किसी भी प्रकार के अनुचित कार्यों में शामिल न किया जाए। उन्हें अधिशेष उत्पन्न करने और अपनी उत्पादकता बढ़ाने में सक्षम होना चाहिए। बहुराज्य सहकारी अधिनियम, 1984 के तहत फेडरेशन एक राष्ट्रीय स्तर की सहकारी शीर्ष संस्था है। आदिवासी सहकारी की अधिकृत शेयर पूंजी 100 करोड़ रुपये है।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के व्यक्तियों के बीच गरीबी की समस्या गंभीर है। यह समस्या उनकी प्रगति और विकास के मार्ग में एक बड़ी बाधा है, इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन उचित तरीके से किया जाए। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम 1980 के दशक से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू किए गए हैं और उन्होंने न केवल गरीबी रेखा से ऊपर उठने के लिए गरीबी से पीड़ित लोगों को सहायता प्रदान की है, बल्कि प्रभावी तरीके से गरीबी दर को कम भी किया है। अन्य पिछड़ा वर्ग इन कार्यक्रमों से काफी हद तक लाभान्वित हुआ है। 1993.94 और 1999.2011 के बीच कुल जनसंख्या की तुलना में गरीबी रेखा से नीचे रहने

वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत के संबंध में गिरावट की दर मामूली अधिक थी। हालांकि, 1999-2011 में कुल जनसंख्या के संबंध में अनुसूचित जातियों के बीच गरीबी की घटना ग्रामीण क्षेत्रों में 36-25% और शहरी क्षेत्रों में 38-47% के साथ क्रमशः 27-09% और 23-62% की तुलना में उच्च बनी हुई है। अनुसूचित जनजातियों के मामले में गिरावट की दर सामान्य जनसंख्या की तुलना में बहुत कम है।

कानूनी सेवा प्राधिकरणों और अधिवक्ताओं द्वारा समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को कानूनी सहायता

भारत के संविधान का अनुच्छेद 39.ए आर्थिक रूप से गरीबी से पीड़ित या अन्य विकलांग नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए समान अवसरों का प्रावधान करने के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है। उन व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता भी प्रदान करता है जो निराश्रित परिस्थितियों में रह रहे हैं। अधिवक्ता अधिनियम, 1961 ने कानूनी सहायता और कानूनी सहायता समितियों की स्थापना के प्रावधानों को भी नियंत्रित किया है। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 को समाज के गरीबी से त्रस्त और जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है। नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 1955 अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली किसी भी विकलांगता के अधीन व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली कानूनी सहायता सहित पर्याप्त सुविधाओं का प्रावधान करता है।

इस अधिनियम के प्रावधान को लागू करते हुए, 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अनुसूचित जातियों और समाज के सामाजिक.आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान करने की योजना शुरू की है। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा, दमन और दीव, दिल्ली और पांडिचेरी। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 और राजस्थान राज्य विधिक सेवा विनियम, 1999 के तहत राजस्थान राज्य में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। कैलेंडर वर्ष 2005 के दौरान, 1048 अनुसूचित जाति और राज्य में 1131 अनुसूचित जनजातियों को कानूनी सेवाओं द्वारा सहायता प्रदान की गई।

कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के नियम 12 के तहत, अनुसूचित जाति के सदस्यों को उनकी आय के बावजूद मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष के दौरान, पंजाब विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जाति के 249 व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की गई। उनके तेजी से विकास के लिए उपरोक्त तरीकों और प्रक्रियाओं के अलावा, भारत का संविधान भी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की सुरक्षा के लिए कई प्रावधान उपलब्ध कराता है।

आदिवासी उप योजना 2010 – 2011

2011 की जनगणना के अनुसार, आदिवासी उप योजना ब्लॉकों में अनुसूचित जनजाति की आबादी 56-31 लाख है जो इन ब्लॉकों की कुल आबादी का 44% से थोड़ा अधिक है। सरकार मुख्य रूप से अनुसूचित जनजातियों के समाज के वंचित वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित है। अनुसूचित जनजातियों की आबादी का एक बड़ा वर्ग दूर.दराज के ग्रामीण गांवों में निवास करता है, जहां ढांचागत सुविधाएं अच्छी तरह से स्थापित नहीं हैं। आदिवासी आबादी के बीच गरीबी की घटना मामूली रूप से अधिक है। आदिवासियों के बीच शिक्षा और साक्षरता की स्थिति 33% जितनी कम है। आदिवासी महिलाओं के मामले में स्थिति और भी खराब है, जिनकी साक्षरता दर 22-11% जितनी कम है (हरियाणा सरकार, 2011)।

उद्देश्य

1. अनुसूचित के लिए रोजगार और आय सृजन गतिविधियों का प्रावधान करना।
2. जनजातियों की जनसंख्या का मुख्य उद्देश्य उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है।

2018-19 और 2019-20 के दौरान उपलब्धि

हरियाणा में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के बीच शिक्षा और साक्षरता कौशल को बढ़ाने के मुख्य उद्देश्य के साथ योजनाओं और कार्यक्रमों की स्थापना की गई है। इन समुदायों के कल्याण में सुधार के लिए शिक्षा में वृद्धि के अलावा, वित्तीय सहायता, मध्याह्न भोजन, साइकिल, आवास और छात्रावास का प्रावधान किया गया है (हरियाणा सरकार, 2011)।

व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाओं में प्रमुख जोर। आदिवासी युवाओं को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण और कौशल विकास के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। जनजातीय समुदायों से संबंधित व्यक्तियों ने शिक्षा के महत्व को पहचाना है। उन्होंने यह जागरूकता उत्पन्न की है कि शिक्षा के माध्यम से वे सभी अनिवार्य क्षेत्रों के बारे में अपनी जानकारी और ज्ञान को बढ़ाएंगे। वे अपने रहने की स्थिति को पर्याप्त रूप से बनाए रखने में सक्षम होंगे। यहां तक कि वे अपने क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं, जहां वे उचित शैक्षिक अवसर पा सकते हैं और पर्याप्त रूप से अपने रहने की स्थिति को बनाए रख सकते हैं। शिक्षा की प्राप्ति व्यक्ति को बेहतर जीवन जीने में सक्षम बनाती है।

अनुसूचित जनजातियों के लिए आवास उपलब्ध कराने के मुख्य उद्देश्य से नए छात्रावासों की स्थापना की गई थी। इसका कारण यह है कि एसटी समुदाय आमतौर पर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवास करते हैं और उन्हें रहने के लिए आवास का प्रावधान करना पड़ता है। इसलिए, छात्रावासों की स्थापना ने उन्हें रहने के लिए जगह प्रदान की। व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहरी क्षेत्रों में प्रवास करते हैं और उन्हें रहने के लिए छात्रावास की सुविधा की आवश्यकता होती है। जामताड़ा और सिमडेगा जिलों में दो नए आश्रम विद्यालयों को अधिकृत किया गया है। इन जिलों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना, जिन व्यक्तियों के पास अन्य क्षेत्रों में प्रवास करने के लिए संसाधन नहीं हैं, वे शिक्षा प्राप्त करने और अपने साक्षरता कौशल को बढ़ाने के लिए इन विद्यालयों में दाखिला लेते हैं।

आवासीय विद्यालयों में भोजन एवं अन्य शर्तों की दरों में सुधार किया गया है। स्कूलों में, छात्रों को पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मध्याह्न भोजन की सुविधा का प्रावधान किया गया है। छात्रों को पर्याप्त पोषण प्राप्त करना महत्वपूर्ण है ताकि वे अपनी पढ़ाई पर अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकें। स्कूलों के भीतर अन्य शर्तों में शामिल हैं, उचित पाठ्यक्रम और निर्देशात्मक प्रणाली, शिक्षण.शिक्षण विधियों, अवसंरचनात्मक सुविधाओं, संसाधनों, उपकरणों और विषय सामग्री का उपयोग करना। शिक्षकों के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि छात्र पाठ्यक्रम को उचित तरीके से समझें और उनका निर्देश पर्याप्त रूप से दिया जाए। राज्य सरकार में वर्ष 2011.12 में 74 पीटीजी युवा स्नातकों का सीधा चयन किया गया है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने आठवीं कक्षा की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाले बेरोजगार पीटीजी युवाओं को नौकरी के अवसरों का प्रावधान करने का निर्णय लिया है। जिन व्यक्तियों ने कम शिक्षा प्राप्त की है उन्हें भी नौकरी प्राप्त करने में सहायता की आवश्यकता होती है और अपना जीवन यापन करने के लिए रोजगार के अवसर मिलते हैं।

मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना . राज्य सरकार द्वारा एक योजना प्रारंभ की जा रही है जिसके तहत अंत्योदय योजना के तहत पीटीजी के लिए तीन रुपये प्रति किलो चावल की सब्सिडी राशि उपलब्ध करायी जा रही है. इस प्रकार, सभी पीटीजी परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलो चावल मुफ्त मिलेगा। वर्ष 2009.10 में 570.00 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है। आठवें नंबर के नए पीटीजी स्कूल इस वित्तीय वर्ष में शुरू किए गए हैं और चयनित गैर.सरकारी संगठनों ने उनके प्रबंधन और प्रशासन का अधिकार ग्रहण किया है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य

पिछड़े वर्गों के बीच शिक्षा और साक्षरता कौशल को बढ़ाने के लिए, प्रशासनिक और प्रबंधकीय कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करना महत्वपूर्ण है।

ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया गया है जिनका उद्देश्य इन व्यक्तियों के बीच शिक्षा को बढ़ाना है। चार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में चालू कलैण्डर वर्ष से प्लस टू कक्षाएं शुरू की गई हैं। वर्ष 2009.10 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्रवृति के रूप में 150.00 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। तथापि, छात्रवृत्ति वितरण की प्रक्रिया अभी भी जारी है। छात्रवृत्ति के प्रावधान का मुख्य कारण इन समुदायों से संबंधित व्यक्तियों की वंचित और गरीबी से त्रस्त स्थिति है। उनके लिए शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति और अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता अनिवार्य है।

अनुसूचित जनजाति के आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र.छात्राओं को साइकिल वितरण के लिए 1296.00 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है. साइकिल को परिवहन का सुविधाजनक साधन माना जाता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से लड़कियों और लड़कों दोनों द्वारा किया जाता है। साइकिलों के उपयोग से वे प्रबंधनीय तरीके से अपने विद्यालयों तक आने.जाने में सक्षम हो जाते हैं। पीटीजी के लिए बिरसा आवास योजना . इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक पीटीजी परिवार को 70,500 रुपये की लागत से आवास सुविधा प्रदान करना है। वित्तीय वर्ष 2009.10 में रू0 1700.00 लाख की स्वीकृति थी। बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति और परिवार रहे हैं, जो बेघर हैं, उनके पास उचित घर और आश्रय नहीं है। इसलिए, इस योजना की शुरुआत के साथ, इन समुदायों के लिए आवास आवास की उपलब्धता हुई है।

अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र.छात्राओं को शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में रू 850.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वे मैट्रिक और इंटर की परीक्षा दे रहे हैं। इन व्यक्तियों के बीच वित्तीय समस्याओं का प्रसार उनके शिक्षा के अधिग्रहण और साक्षरता कौशल के विकास के मार्ग में एक बड़ी बाधा साबित होता है। इस कारण से, लोग स्कूल छोड़ भी देते हैं, लेकिन छात्रवृत्ति की उपलब्धता और किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता, जैसे कि ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति, उन्हें अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाती है।

निष्कर्ष

अनुसूचित जातियों का विकास केंद्र के साथ.साथ राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की पारस्परिक जिम्मेदारी है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण की देखभाल के लिए राज्य सरकारों के अलग.अलग विभाग हैं। हालाँकि, उनका प्रशासनिक ढांचा अलग.अलग राज्यों में अलग.अलग होता है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को प्रोत्साहित करने के लिए कई स्वैच्छिक संगठनों की स्थापना की गई। इन समुदायों की भलाई और प्रगति को बढ़ाने के लिए कई योजनाओं की स्थापना की गई है। प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को छात्रवृत्ति, ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजनाओं का संबंध है। आवास और छात्रावास सुविधाओं को अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि वे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवास करते हैं। इन छात्रों में खेलों के प्रति उत्साह और रुचि पैदा करने की योजनाएँ बनाई गई हैं। योजनाओं का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ये व्यक्ति गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और बेघर होने के परिणामस्वरूप हानिकारक परिणामों का अनुभव न करें। वे मुख्य रूप से गरीबी और पिछड़ेपन की स्थिति को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि ये समुदाय लोगों के अन्य समूहों के साथ संवाद करने में सक्षम हैं, वे शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम हैं और आपस में जागरूकता पैदा करते हैं, रोजगार के अवसर प्राप्त करते हैं और उचित आवास प्राप्त करने में सक्षम हैं और आवासहीनता की समस्या को समाप्त करने के लिए आश्रय।

संदर्भ

[1]. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कल्याणकारी उपाय 03 दिसंबर, 2017 को http://shodhganga-inflibnet-ac- in/bitstream/10603/26529/15/15_chapter%206-pdf से लिया गया।
[2]. अनुसूचित जातिध्अनुसूचित जनजातिध्अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के कल्याण के लिए चलाए गए कार्यक्रम। (रा।) 03 दिसंबर, 2017 को http://commerce-nic-in/publications/pdf/ से लिया गया।
[3]. हरियाणा सरकार। कल्याण विभाग। (2011) 04 दिसंबर, 2017 को पुनःप्राप्त http://documents-gov-in/JH/14567
[4]. कराडे, जे. (एड.) (2008)। भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का विकास।
[5]. कैम्ब्रिज स्कॉलर्स पब्लिशिंग। ttp://www-cambridgescholars-com/download/sample 58518 से 04 दिसंबर, 2017 को लिया गया।
[6]. अनुसूचित जाति के बच्चों के शैक्षिक विकास के लिए नीतियां, कार्यक्रम और योजनाएं। (रा।)। http://www-ncert-nic-in/departments/nie/degsn/pdf_files/degsnmodule 6-pdf से 03 दिसंबर, **2017** को लिया गया।
[7]. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण। (एन.डी.). 04 दिसंबर, 2017 को http://www-spc-tn-gov-in/tenthplan/ से लिया गया।
[8]. कल्याण अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग। (रा।)। http://delhiplanning-nic-in/Write-up/ 2002-03/volume-II/Welfare%20of%20SC-ST-OBC-pdf से 04 दिसंबर, 2017 को लिया गया।